

मुख्य समाचार :-

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया बनाने के मुख्य सचिव को निर्देश दिए।
- भारत और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने अल्मोड़ा के चौबटिया उद्यान, रानीखेत में कीवी की फसल का निरीक्षण किया।
- शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने की देहरादून जिला प्रशासन की पहल। अब जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल माध्यम से होगी पढ़ाई।
- हरिद्वार जिले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों, और होटल-ढाबों में कार्यरत लोगों का सघन सत्यापन किया गया।

प्रादेशिक समाचार के साथ में आणुतोश उनियाल और अब समाचार विस्तार से-

मानक संचालन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी कार्यालयों और कार्यस्थलों पर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए मुख्य सचिव को मानक संचालन प्रक्रिया- एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 21 फरवरी को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में हुई घटना के साथ ही हाल के समय में अन्य स्थानों पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए, ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार कार्मिकों के मान-सम्मान और सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रही है। उन्होंने मुख्य सचिव को दूरभाष पर अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि सरकारी कार्यालयों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही इस तरह की घटनाओं पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी शिक्षा निदेशालय में हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल- आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य की सीमाओं की सुरक्षा, सीमांत क्षेत्रों में विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन में समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में आईटीबीपी के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान न केवल देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों में भी सहभागी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और आईटीबीपी के बीच बेहतर समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने मुख्यमंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं, आधुनिक संसाधनों और बल की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में आपदा प्रबंधन, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में आईटीबीपी की सक्रिय भूमिका पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि "सुरक्षित सीमा, सशक्त उत्तराखंड" के संकल्प के साथ राज्य सरकार सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य कर रही है, ताकि सीमांत क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास की त्रिस्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

कीवी उत्पादन

उत्तराखंड में कीवी उत्पादन की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार और न्यूजीलैंड सरकार के बीच कीवी उत्पादन और तकनीकी सहयोग को लेकर समझौता किया गया है। इसी कड़ी में भारत और न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अल्मोड़ा के चौबटिया उद्यान, रानीखेत में कीवी की फसल का निरीक्षण किया और स्थानीय परिस्थितियों में इसके बेहतर उत्पादन की

संभावनाओं पर चर्चा की। वैज्ञानिकों के दल को यहां की जलवायु, मिट्टी और कीवी उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं न्यूजीलैंड से आए वैज्ञानिकों ने उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीक और बेहतर पैदावार के तरीकों को साझा किया। राजकीय उद्यान समन्वयक डॉ. सुरभि ने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु कीवी उत्पादन के लिए काफी अनुकूल है। न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों के सहयोग से यहां उन्नत तकनीक और बेहतर प्रबंधन पद्धतियां लागू की जाएंगी।

डिजिटल शिक्षा

देहरादून जिला प्रशासन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। इसके तहत अब जिले के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा दी जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले के सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सुविधा विकसित करने के निर्देश दिये हैं। जिला प्रशासन प्रोजेक्ट "उत्कर्ष के तहत सरकारी स्कूलों के लिए 880 स्मार्ट टीवी खरीदे गए हैं, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल, इंटरएक्टिव और दृश्य-आधारित शिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन के इस प्रयासों से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल सामग्री से सीखने का अवसर मिलेगा। साथ ही शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक, प्रभावी और सहभागितापूर्ण बनेगी और शिक्षकों को ऑडियो-विजुअल माध्यम से पढ़ाने में भी सुविधा होगी। इससे ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालय भी तकनीकी रूप से सशक्त होंगे।

सत्यापन अभियान

हरिद्वार जिले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने व्यापक सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के तहत संजय नगर, टिबड़ी और टिहरी विस्थापित कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, मजदूरों, ठेली-फड़ संचालकों और होटल-ढाबों में कार्यरत लोगों का सघन सत्यापन किया गया। पुलिस टीमों ने मौके पर 46 किरायेदारों, मजदूरों और घरेलू नौकरों का सत्यापन किया। साथ ही बिना सत्यापन के किरायेदार, घरेलू नौकर और बाहरी व्यक्तियों को रखने पर पुलिस अधिनियम के अंतर्गत छह मकान मालिकों के साठ हजार रुपये के कोर्ट चालान किए गए। वहीं, पुलिस ने मकान मालिकों को अपने यहां रह रहे किरायेदारों और कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने के निर्देश दिए। साथ ही होटल और ढाबा संचालकों को भी कर्मचारियों का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

घर-घर कूड़ा

नगर निगम देहरादून ने शहर के 100 वार्डों में से 57 वार्डों में कूड़ा शुल्क संग्रहण की जिम्मेदारी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपी है। इन समूहों द्वारा त्रैमासिक आधार पर घर-घर जाकर निर्धारित शुल्क का संग्रहण किया जा रहा है। महिलाओं को संग्रहण शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान मिल रहा है। नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि महिला समूहों द्वारा निर्धारित समय में प्रभावी शुल्क संग्रहण कर निगम को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे राजस्व में वृद्धि के साथ कार्य प्रणाली में भी सुधार हुआ है। वार्ड संख्या 64, नेहरूग्राम की समूह सदस्य सीमा बिष्ट ने कहा कि इस योजना से उनके जैसी अनेक महिलाओं को रोजगार का सशक्त अवसर प्राप्त हुआ है।

वहीं, सहायक नगर आयुक्त राजवीर सिंह चौहान ने बताया कि त्रैमासिक प्रणाली के तहत तीन माह का शुल्क एकमुश्त संग्रहित किया जा रहा है।